

सम्पादकीय

इस माह के आरभ में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आसमान से आग के गोले गिरते दिखाई दिए थे। कई जगह पर प्रत्यक्ष रूप से इन्हें धूरती पर गिरते हुए भी देखा गया। इस तरह की आसमानी घटनाओं के संदर्भ में विज्ञानियों का कहना है कि यह अंतरिक्ष का कचरा या मलबा हो सकता है। अगर यह मलबा ज्यादा बड़े आकार का होता और किसी आवासीय क्षेत्र में गिरता तो यह जानमाल को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता था। दरअसल अंतरिक्ष में एकत्रित हो रहा कचरे का ढेर भविष्य में धूरती पर रह रहे लोगों के साथ-साथ यहां सक्रिय तमाम उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए भी बेहद घातक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे हमारी संचार व्यवस्था के भी प्रभावित होने की आशंका पैदा हो सकती है। ऐसे में जिस तरह से आज आधुनिक तकनीक आधारित तमाम गैजेट्स हमारी दिनचर्यों का हिस्सा बन गए हैं, उससे अलग तरह के नक्सान की आशंका भी हो सकती है। यदि हम अंतरिक्ष में मौजूद तमाम मानव जनित पदार्थी की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक छाटे-बड़े मिलाकर लगभग 17 करोड़ पुराने और नए दोनों तरफे पर्यावरण

राकेट और बाकर हा चुक्त उपग्रहों के दुकड़े आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आपस में टक्कर होने से ये और भी दुकड़ों में बंट रहे हैं जिससे इनकी सज्ज्या में दिनों-दिन बढ़ोतरी ही हो रहा है। ब्रिटिश खगोल विज्ञानी रिचर्ड क्राउटडर के अनुसार इस संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पृथी से 22,300 मील यानी लगभग 36 हजार किलोमीटर ऊपर की भू-स्थैतिक कक्षा में अंतरिक्षीय कर्चरे के जमघट और आपसी टक्कर के परिणामस्वरूप दुनिया की संचार व्यवस्था भी चौपट हो सकती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष में आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर काट रहे सिक्के के आकार के किसी पदार्थ से किसी दूसरे सिक्के के आकार गले पदार्थ की टकराहट होती है तो उससे वैसा ही प्रभाव होगा जैसा धरती पर लगभग सौ किलोमीटर की रफ्तार से चल रही दो बसों की टक्कर से होता है। अंतरिक्ष में तैरते कर्चरे से टकराने पर अंतरिक्ष यान और एकिटर सैटेलाइट्स नष्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही, धरती पर इंटरनेट, जीपीएस, टेलीविजन प्रसारण जैसी

भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी

A vibrant painting of Lord Rama in his Ayodhya avatara, seated on a golden chariot. He is dressed in a red dhoti and a yellow turban, holding a bow and arrow. The chariot is pulled by four white horses and is surrounded by a golden light. In the background, there is a temple structure and a tree.

जब पूरी दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध में उलझी है तो चीन चुपचाप अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने में जुटा है

दुनिया में इन दिनों यूक्रेन पर रूस के हमले की चर्चा है। इसने चीन की एक प्रकार से बड़ी मदद की है कि इस बीच वह बड़ी खामोशी और शांतिर तरीके से एशिया में अपनी विस्तारवादी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। वह अपनी स्थलीय एवं सामुद्रिक सीमाओं को नए सिरे से खींचने के साथ ही ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। रूस के क्षीर्थ सैन्य दाना दशा के बाच हमालया मार्च पर तनातनी बढ़ी है, तबसे उच्च स्तर पर यही सबसे बड़ी मुलाकात हुई है। इन सबसे मामूली समाधान ही निकला है। प्रभावी नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय कानून में क्षेत्रीय दावे में मजबूती का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसीलिए चीन अत्यंत ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में सुनियोजित आदादी को बसाने से लेकर मानव विवादों को बसाने से पूर्व उसे यह लालासल दुगम इलाका में बस्तियां बसाने के रूप में दिखता है, जहां सैन्य-पुलिस पृष्ठभूमि के लोगों को ही सुनियोजित रूप से बसाया जाता है। चीन की रणनीति अपने प्रतिद्वंद्वी की कमज़ोरियों को निशाना बनाकर अपनी मनमर्जी करना है। इसी कड़ी में वह किसी जगह अपना दावा करने से पूर्व उसे विवादित स्वरूप देने में लगा रहता

हमले के उल्ट चीन धोर-धोर यथास्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में लगा है। इसका ताजा उदाहरण चीनी सेना की इस कवायद में दिखता है, जिसमें उसने बड़े गुपचुप तरीके से हिमालयी क्षेत्र के विवादित हिस्सों में 624 गांवों का निर्माण पूरा कर लिया है। ये गांव उस सीमा में बने हैं, जिन्हें भारत, नेपाल और भूटान अपना हिस्सा मानते हैं। ऐसे सैन्य गांव वास्तव में दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए गए क्रिम द्वीपों की भाँति हैं, जो उसके लिए अर्गिम मोर्चों की भूमिका निभा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारत के साथ चल रहे सैन्य टकराव के बीच भी चीन इन गांवों के विकास में सफल रहा। दोनों देशों की सेनाओं में पिछले करीब दो वर्षों से संघर्ष जारी है। इस दौरान चीन ने लद्धाख के कुछ इलाकों में घुसपैठ का प्रयास किया तो भारत की ओर से भी उसे करारा जवाब मिला। सैन्य तनाव को घटाने के लिए सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता जारी है। हाल में विदेश मंत्री एस. जराणाकर और चीनी विदेश मंत्री निमित द्वारों का निर्माण कर रहा है। यह चीनी राष्ट्रपति शी चिन्फग की विस्तारवादी नीति का अहम हिस्सा है। शी के इस विस्तारवाद ने भूटान जैसे बेहद छोटे से देश को भी नहीं बच्चा। चीन ने यथास्थिति को एकत्रफा रूप से न बदलने संबंधी 1998 के द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया। अब भूटान की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चीन के कई सैन्य गांव बस गए हैं। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान करीब चार दशकों से चीन के साथ बातचीत कर रहा है। चीन का यह विस्तारवाद कई परतों वाली रणनीति के तहत संचालित होता है। इसमें सबसे पहले किसी इलाके पर दावा किया जाता है। फिर उसके ईर्दगिर्द वह पूरा प्रपञ्च रचता है, जिसमें किसी प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। दक्षिण चीन सागर का ही उदाहरण लें। उसमें आपको कई परतों दिखाई देंगी। मसलन वहां चीनी मछुआरों की नारें, तटरक्षक पोत और जीसेना के जड़ानों की पक्की

ताम भा द दिया ह। जहा चान न
यहां अपने युद्धपोत और बड़े जहाज
भेजना शुरू कर दिया, वहीं जापान
सेनकाकू पर लाइटहाउस के निर्माण
जैसी रक्षात्मक मुद्रा अपनाने तक
सीमित रह गया। वास्तव में किसी
जापानी रक्षा मंत्री ने निर्जन सेनकाकू
ट्रिप का हवाई सर्वेक्षण तक नहीं
किया। इसके पीछे यहीं उज रही
होगी कि बीन कहीं उसे किसी प्रकार

रह। प्रातद्वद्वा का टकनार लगाकर शी सभी विकल्प अपने पास रखना चाहते हैं। इसमें सैन्य टकराव बढ़ने की स्थिति में एकाएक हमले से चौकाने का विकल्प भी शामिल है। इसमें युद्ध शुरू करने का ठीकरा भी दूसरे पक्ष पर फोड़ा जा सकता है। अंतराराष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी क्षेत्रीय दावा संबंधित क्षेत्र में संप्रभुता को लेकर निरंतर एवं

गरकानूना कृत्या आर दावा का लकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ताल मिलाने के लिए चीन घरेलू स्तर पर नए कानून बना रहा है। दक्षिण चीन सागर में मानव निर्मित द्वीपों और नए प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना से लेकर हिमालयी क्षेत्र में गांवों की स्थापना इसी रणनीति को सिरे ढाने का हिस्सा है। हिमालयी क्षेत्र में चीन के रहस्यमयी वित्तीय

दायरा इन 624 सीमावर्ती गांवों से आगे जाता है। चीन विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सेन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी जुटा है, ताकि टकराव की स्थिति में सैनिकों एवं सेन्य साजोसामान को तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। भूतान की सीमा से मुजररे वाली नई चीनी सड़क से भारत के संरेतनशील बिंदु 'सिलिगुड़ी कारिडोर' को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ी है। यही कारिडोर पूर्वीतर को शेष भारत से जोड़ता है। दिलचस्प बात यही है कि चीन अपने ऐसे मंसूबे बिना कोई गोली दागे पूरे करता दिख रहा है और उसे यह परवाह नहीं कि वह एक साथ दो मर्दीय पर भी उलझ सकता है। पैट्रागन की एक रपट के अनुसार, 'चीन भारत के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ किसी सूखे में ताइवान को लेकर उपजने वाली आपात स्थिति से निपटने की भी तैयारी कर रहा है।' कुल मिलाकर दुनिया में अर्थिक रूप से सबसे गतिशील क्षेत्र एशिया में चीन की बढ़नीयती असुरक्षा को ही बढ़ाने का काम कर रही है।

है, जो कि पूर्णतः गलत है। मुस्लिम बहुत्य कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68.31 प्रतिशत है, पर उर्दू को अपनी मातृभाषा लिखाने वाले मात्र 0.23 प्रतिशत ही है। असम में मुस्लिम जनसंख्या 34.22 प्रतिशत है, पर जिन्होंने अपनी मातृभाषा उर्दू लिखवाई है, उनका प्रतिशत मात्र 0.06 है। बंगाल में भी मुस्लिम आबादी 27.01 प्रतिशत है, पर मातृभाषा उर्दू लिखाने वालों की संख्या मात्र 6.74 प्रतिशत ही है। यानी संविधान के अनुच्छेद-29 एवं 30 में जिस भाषा और लिपि को अल्पसंख्यक मानकर संरक्षण देने की बात है, उसमें मुसलमान नहीं आते, क्योंकि वे जिस राज्य में रहते हैं वहां के लोगों की मातृभाषा को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं। कुल मिलाकर देश में कौन-कहाँ अल्पसंख्यक हैं इसकी घोषणा और उनकी सुरक्षा तथा विकास का विचार सतही स्तर पर न करके सूक्ष्म स्तर पर होना चाहिए। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 की आड़ लेकर शिक्षा के नाम पर जो विषयमन और धंधा किया जा रहा है, उस पर भी कड़ाई से रोक लगाई जाना चाहिए।

जहां हिंदुओं वालपाडा, बारपेटा, मोरीगांव, नवांग, करीमगंज, हैलाकांडी, बोंगाईगांव एवं दरांग, बंगल के मालदा, मुर्शिदाबाद एवं उत्तर दिनाजपुर, झारखण्ड के मालुकु, लोहरदगा, खुंटी, गुमला, सिमड़ेंगा एवं पश्चिमी सिंहभूम, तपिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के वायनाड, मल्लपुरम, एनाकुलम, हिंडुकी एवं कोडुग्यम जिलों में हिंदुओं की आबादी 50 प्रतिशत से कम है। ऐसे में समय की मांग है कि अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान राज्य या जिला नहीं, बल्कि प्रखण्ड/सर्बाधिविजन और सर्किल स्तर पर की जाए, क्योंकि देश के अनेक ऐसे जिले हैं, जहां जिला स्तर पर भले ही हिंदू बहुमत में हैं, पर इससे नीचे बड़े भूभाग में वे अल्पमत में हैं और असुरक्षित हैं। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छह सर्बाधिविजन हैं, लेकिन छह में से चार-ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, संभल और बिलारी में वे अल्पमत में हैं। बंगल के उत्तर 24 परगना में नौ, दक्षिण 24 परगना में सात प्रखण्ड और असम के कछार जिला के पांच सर्किल में से दो में हिंदू अल्पमत में हैं। जिन राज्यों/जिलों/सर्बाधिविजन में मुस्लिम और इसाई बहुमत में है,

वहां से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन का पलायन हो रहा है, क्योंकि वहां वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद-29 एवं 30 में भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान के संचालन की बात कही गई थी, पर बाद में केंद्र और राज्य सरकारें तुष्टीकरण के तहत अल्पसंख्यक मत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग गठित करती चली गई। तुष्टीकरण का वीभत्स रूप तब सामने आया जब पूर्ण प्रथानमंत्री मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि संसाधनों पर पहला अधिकार 'अल्पसंख्यकों' का है। सर्वीच्य न्यायालय में दायर केंद्र सरकार के हलफनामे में भी राज्य सरकारों को 'भाषाई' अल्पसंख्यक घोषित करने की बात कही गई है, जबकि अल्पसंख्यक नाम लेकर पंथिक/धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की जाती है। देश में अल्पसंख्यक का अर्थ मुस्लिम और ईसाई से लगाया जाता है। सवाल है कि क्या मुसलमानों या ईसाइयों की कोई अपनी भाषा या लिपि है, जिसके संरक्षण की आवश्यकता है? कई बार उर्दू को मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता

